आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 30.04.2023 से 07.05.2023)

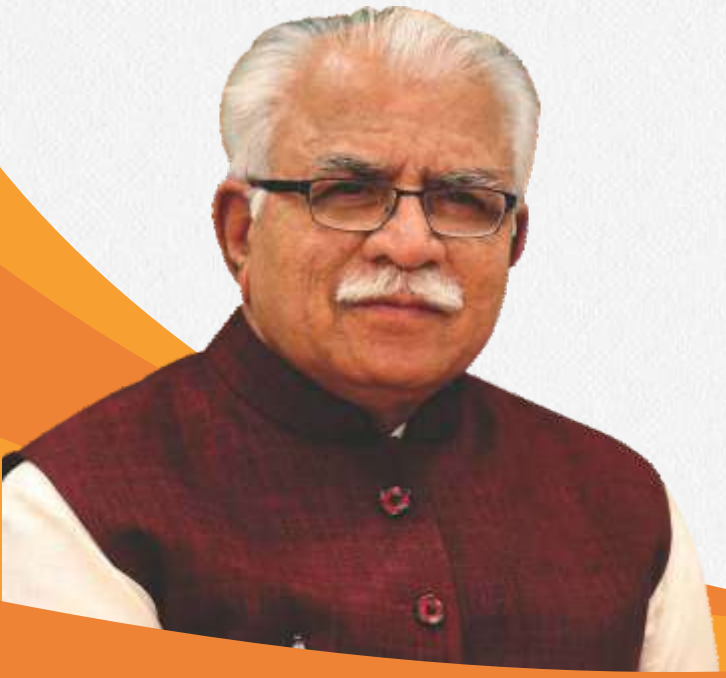

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकारों से संवाद

(दिनांक 30.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां गुड गवर्नेंस पहलों के अध्ययन के लिए पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के अंतर्गत देश भर से आए वरिष्ठ पत्रकारों के एक दल से संवाद कर कहा कि जन सेवा सर्वोपरि के हमारे ध्येय के अनुरूप राज्य सरकार ने 'शासन कम– सुशासन अधिकतम' को मूर्तरूप देने के लिए अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया है, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। प्रदेश की अनेक अनूठी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और अन्य प्रदेशों ने भी उन योजनाओं को अपनाया है। इस दल में विभिन्न प्रांतों के 20 से अधिक वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। दल ने तीन दिन तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर गुड गवर्नेंस से जुड़े कार्यक्रमों व स्कीमों का धरातल पर जाकर अध्यन्न किया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

दल के प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए कहा कि देश में अपनी तरह की अनूठी योजना परिवार पहचान पत्र हरियाणा में लागू की गई है। इस योजना ने पूरे दल को सबसे अधिक प्रभावित किया है।

इस बारे अधिक जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने परिवार को एक इकाई मानते हुए हर परिवार का डाटा एकत्र किया और सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया है। अब सभी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को घर बैठे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीपीपी के माध्यम से साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही, एससी, बीसी इत्यादि सर्टिफिकेट भी मात्र एक क्लिक से मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए थे ऑनलाइन ट्रांसफर नीति बनाई इस नीति के तहत अध्यापकों को उनके द्वारा भरे गए टॉप से विकल्पों में से एक स्टेशन मिलता है इस नीति से लगभग 94 प्रतिशत अध्यापक संतुष्ट है। हरियाणा की इस नीति का भी अन्य

साप्ताहिक सूचना पत्र

राज्य अनुसरण कर रहे हैं। पानी के सदुपयोग के महत्व को लेकर हरियाणा में लागू की जा रही मेरा पानी–मेरी विरासत योजना का जिक्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पानी के संकट को देखते हुए जल संरक्षण हेतू मेरा पानी–मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य कम पानी वाली फसल की बिजाई करने पर किसान को 7000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। दल के प्रतिनिधियों ने 'म्हारा गांव–जगमग गांव' योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि हरियाणा की यह योजना अपने आप में अनुकरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस योजना के तहत बिजली चोरी पर अंकुश लगाते हुए गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है।

इस दल ने अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान सोनीपत के गांव अटेरना, बरोटा, करनाल के गांव पाढा व काछवा और पंचकूला में डायल–112 मुख्यालय का

दौरा कर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बारीकी से अध्ययन किया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दल के सभी प्रतिनिधियों को हरियाणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राखीगढ़ी से संबंधित स्मृति चिह्न भेंट किए। साथ ही, प्रतिनिधियों को सरकार के सफल 8 सालों के कार्यकाल में हासिल उपलब्धियों पर तैयार कॉफी टेबल बुक भी वितरित की गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

एचकेआरएनएल एंटरप्राइजेज पोर्टल का लॉन्च

(दिनांक 30.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संस्थागत तरीके से निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एचकेआरएनएल एंटरप्राइजेज पोर्टल लॉन्च किया है। अभी तक विभिन्न कंपनियों से आई लगभग 6000 मैनपावर की मांग के अनुरूप आज 12 हज़ार से अधिक युवाओं को कंपनियों में इंटरव्यू के लिए ऑफर भेजा गया है। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े उद्योगपतियों, विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उद्योग काफी समय से इस प्रकार की योजना या पहल चाहते थे। आज इस पोर्टल की शुरुआत से उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पोर्टल पर उद्योगपति पंजीकरण करा सकते हैं और मैनपावर की मांग भेज सकते हैं। रोजगार

योग्य उम्मीदवार भी स्वयं को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एचकेआरएनएल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित उद्योगों द्वारा मांग की गई मैनपावर के अनुपात के अनुसार उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, एचकेआरएनएल कुशल, अर्ध कुशल व अकुशल मैनपावर के लिए 12,000 से 30,000 रुपये तक विभिन्न वेतन स्लैब में रोजगार प्रदान करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है।

पहले वर्ष में लगभग 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी–1 के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसलिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने किया है। अब आउटर्सासिंग पॉलिसी–1 के तहत सभी अनुबंध कर्मचारिया की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि रोजगार सृजन अनुदान योजना के तहत कई ब्लॉक में सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े एवं मेगा परियोजनाओं की नई स्थापित इकाइयों को 7 साल के लिए कुशल,अर्धकुशल व अकुशल श्रेणियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एचकेआरएनएल संबंधित शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उद्योग की मांग के अनुसार उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण देगा। इसके लिए एचकेआरएनएल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जैसे अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से मैनपावर के लिए प्रशिक्षण व प्रमाणन की व्यवस्था करेगा। कौशल विश्वविद्यालय ने 50 से अधिक कंपनियों के साथ एमओयू किया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

कुरुक्षेत्र जन संवाद कार्यक्रम

(दिनांक 01.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज सोमवार को कुरुक्षेत्र जिला के अपने तीन दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला के पहले दिन गांव झांसा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में कहा कि स्वास्थ्य–शिक्षा सहित अंत्योदय की भावना से हरियाणा सरकार जनहित पर विशेष ध्यान दे रही है। गांव में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने स्वागत किया। हरियाणा एक–हरियाणवी एक मेरे लिए केवल नारा नहीं, मेरा संकल्प है और पिछले 8 सालों से इसी मूल मंत्र को लेकर हरियाणा की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत तंत्र विकसित किया जा रहा है। पूर्व सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार के साढ़े 8 साल में आधारभूत ढांचागत विकास सहित अन्य जनहितकारी योजनाओं में आमजन को सीधा लाभ दिया जा रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांव झांसा में हाल ही में एक करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने गांव में 8 लाख रुपये की राशि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही रेडियोग्राफर की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास पर फोकस कर रही है और ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शी ढंग से विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इन साढ़े 8 सालों में पूर्व की सरकारों के अधूरे विकास कार्यों को भी पूरा करने का काम किया गया है। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि करीब 1840 परिवारों की आबादी वाले झांसा गांव में 3452 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गए हैं और उनमें से अब तक 411 लोगों ने आयुष्मान चिरायु योजना के तहत करीब 71 लाख रुपये की राशि का

साप्ताहिक सूचना पत्र

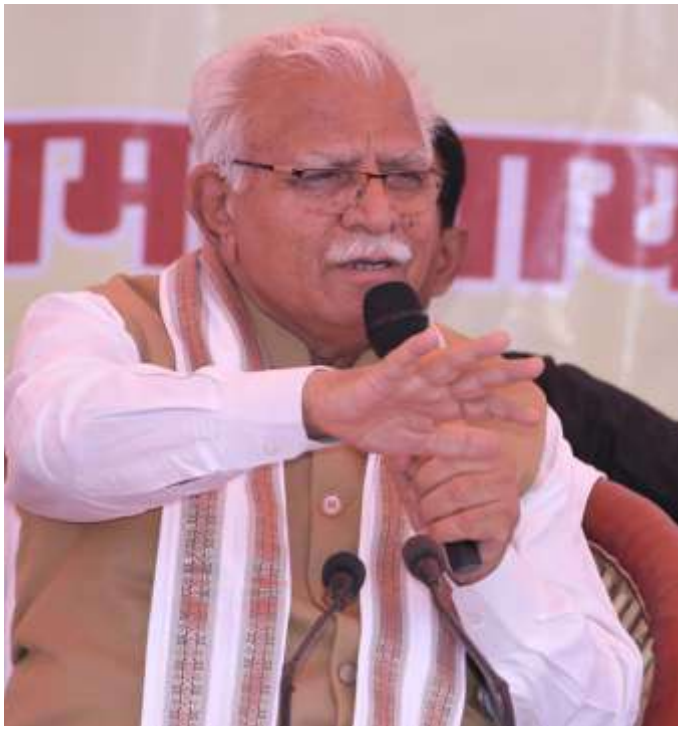

इलाज मुफ्त करवाया है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत 1.80 लाख रुपये की कम आय वालों के स्वतरू ही नए राशन कार्ड बन रहे हैं।

उन्होंने बताया कि योग्यता के आधार पर नौकरी लग रही है और झांसा में अब तक इस सरकार के कार्यकाल में 62 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सरकार की ओर से अब 60 साल से अधिक आयु होने पर अपने आप ही पेंशन बन रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गांव झांसा में 2685 लोगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोड़ते हुए स्वरोजगार प्रदान किया है और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने सराहनीय कदम उठाए हैं।

इस अवसर पर गांव झांसा में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत बनी नई अनाज मंडी फेज–2 के करीब 6.38 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान हित में विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इन विकास कार्यों से किसानों को मंडी में अपनी फसल की बिक्री के दौरान हर सम्भव सुविधाएं मिलेंगी। आढ़तियों व किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में नई अनाज मंडी फेज–2 का निर्माण 8 एकड़ 2 कनाल 6 मरला में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 6 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से तीन इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कवर्ड शेड, दो पार्किंग, पानी आपूर्ति व सीवरेज सिस्टम तैयार किया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा के जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की वृद्धि

(दिनांक 02.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार जीएसटी कलेक्शन में बेहतरीन कार्य कर रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हरियाणा के जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में राज्य का जीएसटी कलेक्शन जहां 8,197 करोड़ था, वहीं वर्ष 2023 में यह बढक़र 10,035 करोड़ हो गया है। जीएसटी कलेक्शन के संबंध में हरियाणा की तुलना अगर पड़ोसी राज्यों से करें तो पंजाब में 16 प्रतिशत, हिमाचल में 17 प्रतिशत, दिल्ली में 8 प्रतिशत और राजस्थान में 5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर खुशी जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति कि है जो कि प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आर्थिक विकास के मापदंडों

पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार बड़े उद्योगों के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी महत्व दे रही है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली उपलब्धता और कनेक्टिविटी में सुधार किया है। पूरे प्रदेश में सडक़ों व रेलमार्गों का जाल बिछा हुआ है। देश में एक देश–एक कर की अवधारणा पर लागू जीएसटी प्रणाली बेहद कारगर है। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होने से न केवल उद्यमियों को फायदा पहुंचा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव

(दिनांक 04.05.2023)

प्रभाव : संतों व महापुरुषों की राज्य स्तर पर जयंती मनाने की परंपरा की कड़ी में आज करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगाकर योगी समाज को कृतार्थ किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक पीठ (चेयर) स्थापित की जाएगी, जो उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर शोध करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की कि नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी–पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में बीसी (ए) वर्ग को आरक्षण प्रदान किया था। अब नगर निकायों में

भी इसी तर्ज पर बीसी (ए) वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को बाबा गोरखनाथ की शिक्षाओं से अवगत करवाने के लिए गुरु गोरखनाथ की जीवनी व उनकी शिक्षाओं का उल्लेख स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योगी समाज जहां सहमति प्रदान करेगा, उन शहरों में गुरु गोरखनाथ के नाम पर चौक या मार्गों का नाम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी समाज के लोग अपनी धर्मशालाओं की सूची प्रदान कर दें, जहां भी जो आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने में हमारे संत–महापुरुषों का सदैव अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, इसलिए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने संत–महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु संत–महापुरुष सम्मान एवं प्रचार–प्रसार योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी संत–महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। आज का यह स्मृति उत्सव भी इसी कड़ी में आयोजित किया गया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय कर्ण कमल का उद्घाटन

(दिनांक 04.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज वीरवार को करनाल सेक्टर 9 स्थित भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय कर्ण कमल के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा कि पिछले साढ़े 8 वर्षों में सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक विकासात्मक परियोजनाएं तथा जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है जिनका प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र अनियमितताओं व गड़बड़ियों को पकड़ने में अहम दस्तावेज साबित हुआ है जिसका अध्यन्न करने में देश के पांच–छः राज्यों सहित कुछ विदेशी देशों ने भी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किये गए सर्वे के आधार पर प्रदेश में 12 लाख 50 हजार नए बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार

के 1 लाख 20 हजार रुपये की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख 80 रुपये करने के फलस्वरूप प्रदेश में आयुष्मान कार्ड एवं चिरायु हरियाणा योजना के तहत 7 लाख लोगों ने मुफ्त में अपना इलाज करवाया है, जिस पर 950 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है जिसके सक्रिय सदस्यों की संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी कहीं अधिक है।

इसलिए पार्टी कार्यकर्ता सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाएं ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी कार्यालय के भवन का उद्घाटन होना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है और यह दिन कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन बन जाता है, क्योंकि पार्टी को सुचारू रूप से चलाने एवं मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं का बहुत ही महत्व है। उन्होंने कहा कि आज का यह उत्सव सब कार्यकर्ताओं की बदौलत है, जिन्होंने इस कार्य में अपना योगदान दिया, इसे बनाकर तैयार किया है और जिसका नाम कर्ण कमल रखा गया है। इस नाम में भी एक ताकत है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि दानवीर कर्ण नगरी करनाल में पार्टी कार्यालय का नाम भी कर्ण के नाम रखा है जो इस शहर की शान है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान पर विशेष बैठक का आयोजन

(दिनांक 05.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने निवास संत कबीर कुटीर पर संत महात्माओं के साथ जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान विषय पर विशेष बैठक का आयोजन कर कहा कि अनंतकाल से संत महापुरुषों ने सदैव सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जन को जागरूक करने का काम किया है। जन मानस संत महापुरुषों के विचारों और शिक्षाओं को मानते हुए सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में भरपूर सहयोग देते हैं। इसलिए संत महापुरुषों का जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान में राज्य सरकार के साथ सहयोग करने से यह अभियान निश्चित तौर पर सफल होंगे। संत महात्माओं ने हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण और नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना की और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन दोनों पुण्य कार्यों

साप्ताहिक सूचना पत्र

की सफलता के लिए अपनी ओर से सहयोग देने का भरोसा दिया।

बैठक के दौरान सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश खुल्लर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नशे की समस्या की वास्तविकता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार नशा तस्करों पर सख़्त कार्रवाई कर रही है। इसके लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सैल्स बनाए हैं और हरियाणा में 5 हजार से अधिक गिरफ्तारियां की गई है। जनवरी, 2023 तक नशा अपराधों में शामिल व्यक्तियों की 37.29 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है और 15 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया जारी है। अपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है तथा पंचकूला में अन्तर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है।

उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। नशा मुक्ति व पुनर्वास हेतु प्रदेश में 52 नशा मुक्ति केंद्र

खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कालेजों में भी नशा मुक्ति वार्ड खोले गए हैं और 13 जिलों के सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार सरकार जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए ग्राम से राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया है। टोल फ्री एंटी – ड्रग हेल्पलाइन नंबर 9050891508 शुरू किया गया है, जिस पर नागरिक सूचनाएं दे सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को नशे से बचाने के लिए कार्यक्रम धाकड़ भी चलाया जा रहा है। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (सिंचाई) श्री देवेंद्र सिंह ने संतों को अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जल संरक्षण के प्रति बेहद गंभीर हैं। उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में विभिन्न विभागों, हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ जल संरक्षण पर 2 दिवसीय जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में जल संरक्षण और जल संचयन के लिए भविष्य की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हरियाणा जल संरक्षण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

तीर्थ दर्शन योजना की शुरआत

(दिनांक 05.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना 70वां जन्मदिन पंचकूला के सेक्टर–15 स्थित शिशु गृह में बड़ी सादगी से मनाया अपने जन्म दिवस पर बुजर्गों तोहफ़ा देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या यात्रा के लिए आज पंचकूला से बस को झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। लगभग 200 वृद्धजन 5 मई से 8 मई तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा करेंगे। यह बस पंचकूला से अंबाला कैंट तक पहुंचेगी और अंबाला से रेल के माध्यम से ये यात्री अयोध्या तक का सफर तय करेंगे। इन यात्रियों का आने जाने का खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहां की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की

शुरुआत आज पंचकूला जिला से को जा रही है। इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उसके बाद 60 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेगा उन्हें भेजने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करने का सपना होता है, इसलिए सरकार ने यह योजना बनाई है। इस योजना के तहत सबसे पहले अयोध्या यात्रा की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से हमें मर्यादाएं सीखने को मिलती हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा अभियान चला और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। आज श्री राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो रहा है। भावी पीढ़ियों को भी यह जानने का मौका मिलेगा कि भारत में श्री राम मंदिर के लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। वरिष्ठ नागरिकों ने 'राम को लाएं हैं, हम उनको लाएंगे' के नारे लगाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

साप्ताहिक सूचना पत्र

सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशासनिक सचिवों की बैठक

(दिनांक 06.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। 2015 में पुन्हाना में वेयरहाउस बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में हुई देरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक सचिव को एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम घोषणाओं के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, सिंचाई, खेल विभाग और शहरी स्थाानीय निकाय विभागों की परियोनाओं की समीक्षा की। प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा, वर्ष 2021, 2022 की परियोजनाओं के

क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे स्वयं सीएम घोषणाओं की नियमित समीक्षा बैठकें करें। इसके साथ ही, सभी परियोजनाओं के लिए पीईआरटी चार्ट तैयार करें, ताकि परियोजनाओं की समयावधि और पूर्ण प्रतिशतता की स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा, जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए।

बैठक में हकीकत नगर करनाल में प्राईमरी स्कूल खोलने की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर अधिकारियों ने बताया कि इस गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल शुरू हो जाएगा। सिवानी तहसील के कुछ गांवों को भिवानी जिले से हिसार जिले में शामिल करने की सीएम घोषणा पर समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इसके लिए एक टीम गठित की जाए और इन सभी गांवों के सरपंचों के साथ ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर वहां के लोगों की सहमति प्राप्त की जाए, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, अनाज मंडी, डबवाली में प्लेटफार्म बनाने के संबंध में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में आज शाम तक प्रक्रिया पूरी की जाए और कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। विभिन्न स्थानों पर ऑफिसर्स आवास बनाने की घोषणाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सब–डिविजन पर ऑफिसर्स आवास या फ्लैट बनाने के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि अधिकारियों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो सके और उप मंडल का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में जिला मुख्यालय से अधिक दूरी वाले सब–डिविजनों के लिए कार्य

योजना तैयार की जाए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि गांवों में बने पार्क एवं व्यायामशालाओं के रख–रखाव की जिम्मेवारी आयुष विभाग को सौंपी जाए। गांवों में जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, उसके लिए भूमि की खरीद दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए सरपंचों व जिला परिषदों को शामिल किया जाए। विभिन्न सड़कों की मरम्मत व नई सड़कों के निमार्ण संबंधी घोषणाओं पर उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता पुरानी सड़कों के मरम्मत के कार्य को दी जाएगी। उसके बाद आवश्यकता व मांग अनुसार नई सड़क का निमार्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों के रख–रखाव का कार्य जिला परिषद द्वारा किया जाएगा।

यह भी निर्देश दिये कि सड़क मार्गों की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर एनएचएआई के साथ बैठक की जाए ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके। बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष 2014–2023 तक कुल 9962 सीएम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 6555 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। 1179 अभी प्रगति पर हैं।

ई–फर्द के लाभार्थियों से सीधा संवाद

(दिनांक 06.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई–फर्द सुविधा का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद कर कहा कि ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई–फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि https:@@jamabandi-nic-in पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द अर्थात् नकल प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटान के लिए सांझी खेवट की तकसीम हेतू प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अदालतों में लंबे समय तक

चलने वाले जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी।

लाभार्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने ई–फर्द प्रणाली लागू करके आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत दी है। क्योंकि पहले फर्द प्राप्त करने के लिए पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, यहां तक कि महीनों महीनों का समय लगता था लेकिन अब यह काम घर बैठे मिनटों में ही हो जाता

है। लाभार्थियों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार आप लोगों की सुविधा के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये काम ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही होने लगेंगे। सरकार का यह कदम क्रांतिकारी कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 25 दिसम्बर, 2022 का https:@@jamabandi-nic-in पोर्टल शुरू किया था और यह खुशी की बात है कि पिछले 4 माह में लगभग 10 हजार लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई–फर्द ऑनलाइन डाउनलोड की है। उन्होंने कहा कि एक फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपये है और पहले खेवट के लिए 10 रुपये तथा इसके बाद के प्रत्येक खेवट के लिए 5 रुपये फीस देनी होती है।

उन्होंने कहा कि पहले इस काम के लिए दलाल कमीशन लिया करते थे, लेकिन अब ऐसे दलालों से मुक्ति मिली है और इस प्रकार के काम घर बैठे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब हम सत्ता में आए, तो उस समय हमारा उद्देश्य यही था कि किस प्रकार आम जनता की समस्याओं को दूर कर उनके जीवन को सरल बनाया जाए। इसके लिए डिजिटल सिस्टम खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड सम्बन्धी जानकारी के लिए सिंगल विंडो का काम करता है। इस पोर्टल पर ही ई – फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि खसरा , खतौनी जमीन का नक्शा , प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क कैलकुलेटर आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेशभर की सभी 143 तहसीलों / उप तहसीलों में वैब– हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है। सभी राजस्व रिकॉर्ड रूम का भी कम्प्यूटरीकरण कर दिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों तथा राज्य मुख्यालय पर डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए थे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नवनियुक्त बीडीपीओ के साथ चर्चा

(दिनांक 07.05.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां हरियाणा निवास में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के नए बैच में चयनित एवं नियुक्त अधिकारियों के साथ परिचय कर कहा कि सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र के ग्राम सचिव एवं सरपंचों से मिलकर उनके गांव का 'ग्राम पंचायत डिवलेपमैंट प्लान' (जीपीडीपी) तैयार करवाएं और जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड करवाएं। उन्होंने घोषणा की कि आवश्यतानुसार राज्य में खंड स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के सरकारी आवास बनाए जाएंगे। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों से एक–एक करके परिचय किया और उनको ईमानदारी एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। खंड विकास पंचायत अधिकारियों के वर्ष 2023 के बैच में कुल 46 खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों का

चयन हुआ है। इनमें एमबीबीएस डॉक्टर से लेकर एमटेक, एमएससी, लॉ डिग्री धारकों के अलावा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवनियुक्त खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को राज्य सरकार की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इन्हें पारदर्शी एवं ईमानदारी तरीके से लागू करके अपनी प्रतिभा का परिचय देने की आपकी बारी है। उन्होंने पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत से तालमेल करके तटस्थ होकर काम करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी को इनोवेटिव आइडिया सूझता है तो वह अपने वरिष्ठड्ड अधिकारियों से अवश्य शेयर करे ताकि विश्वसनीयता पाए जाने पर पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की ग्राम स्तर पर प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों में तालाबों की सफाई, शिवधाम का रखरखाव, पार्क–व्यायामशाला व वेलेनेस सैंटर का निर्माण आदि कार्य करवाए जा रहे हैं, ऐसे में सभी नए नियुक्त खंड विकास पंचायत अधिकारी इन कार्यों में रूचि लेकर काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर जी ने नए खंड विकास पंचायत अधिकारियों को ग्रामीण स्तर के परिवार पहचान पत्र के बकाया रजिस्ट्रेशन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरपंचों व ग्राम सचिव से मिलकर स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी आईडी के रजिस्ट्रेशन को भी स्पीड अप करने के निर्देश दिए।